RNI Regn.No.- 54447/78 स्थापित: 1978 Postal Reg. No. UA/NTL- 08/ 2024-26

पिघलता हिमालय

वर्ष 39 अंक 19 हल्द्वानी सम्वत् 2080 सोमवार 16 अक्टूबर 2023 एक प्रति 5 रु., वार्षिक-200 रु. आजीवन 2000 रु.

संस्थापक- स्व.आनन्द बल्लभ उप्रेती
स्व.दुर्गा सिंह मर्तोलिया,
स्व.श्रीमती कमला उप्रेती

editorpighaltahimalay@gmail.com
Website-
www.pighaltahimalay.com

सम्पादक : श्रीमती गीता उप्रेती
संरक्षक : फली सिंह दत्ताल
मंगल सिंह मर्तोलिया

हिमालय से चुनाव का बिगुल बजा गये मोदी

कार्यालय प्रतिनिधि

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस बार हिमालय से चुनाव का बिगुल बजा गये हैं। अपने दौरे में आदि कैलास से लेकर जागेश्वर तक वह शिवमय रहे और 4200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। सोर घाटी पिथौरागढ़ में विशाल जनसभा को सम्बोधित किया और दुनिया में भारत के डंके बात कही। पीएम के दौरे से जनता में उत्साह जगा कि सीमान्त क्षेत्र से लेकर दुर्गम स्थानों में गतिविधियां होंगी। यही कारण था कि प्रधानमंत्री के दौरे के अन्तिम समय तक भी लोग अपनी बात उन तक पहुँचाना चाहते थे और प्रशासनिक तैयारियों के साथ अपनी ओर से मिलने की उत्सुकता थी। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद कहा जा रहा है कि धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में मानसखण्ड भी केदारखण्ड की तरह प्रचार पायेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रधानमंत्री के इस दौरे को उत्तराखण्ड के लिये नई शुरुआत माना है। सीएम ने प्रधानमंत्री की अगुवाई करते हुए इन महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बताया।

पीएम मोदी की सोर घाटी जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में हुई सभा को सुनने के लिये अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र की 14 विधानसभाओं के लोग पहँचे थे। इसके अलावा देशभर के तमाम स्थानों से महानुभाव पधारे थे।

मोदी के दौरे को लेकर कहा जा रहा है कि वह लोकसभा चुनाव का टॉनिक दे गये हैं। जिस प्रकार प्रदेश की पूरी कैबिनेट पिथौरागढ़ में जुटी उससे यह अनुमान लगाना बहुत आसान है कि चुनाव से पहले गोटियां सरक रही हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा का कहना है कि मोदी शिव के भरोसे वैतरणी पार कराने आए थे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी इसे करतब करार दिया है।

पसकने-परोसने की होड़

नेताओं/माननीयों/अधिकारियों के सामने पसकने-परोसने की होड़ बढ़ती जा रही है। फिर अति विशिष्ट व्यक्ति के आगमन पर तो यह अवसर पाने के लिये ज्यादा ही होने लगता है। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर भी ऐसा देखा गया।

ज्ञापनों के पुलिंदे पीएमओ को

प्रधानमंत्री मोदी का आना जब तय भी नहीं हुआ था तभी से सीमान्त क्षेत्र से अलग-अलग मामलों को लेकर ज्ञापनों के पुलिन्दे प्रधानमंत्री कार्यालय को डाक द्वारा भेजे जाने लगे थे। सीमान्त की घाटियों से जुड़े विभिन्न संगठनों-संस्थाओं की ओर से प्रशंसा के पत्र और जन समस्याओं की चर्चा इनमें की गई है।

पहाड़ी रसोई का प्रचार-प्रसार

मोदी के आगमन पर पहाड़ी रसोई का खूब प्रचार-प्रसार हुआ। भट की चुड़कानी, गहत की दाल, झोली-भात से लेकर तमाम व्यंजनों की चर्चा कई दिन से अखबारों में होने लगी थी और इन्हें परोसा भी गया।

प्रदेश के सारे मंत्री सोर पहुँचे

प्रधानमंत्री के दौरे में उत्तराखण्ड के सभी मंत्री सोर घाटी पहुँचे। दौरे से पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट, कबीना मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, रेखा आर्य, सांसद अजय टम्टा तैयारियों को परखने पहुँचे थे।

छलिया कलाकारों के बहाने

प्रधानमंत्री के स्वागत के लिये पिथौरागढ़ में तमाम जगह से छलिया नर्तकों के दलों को बुलाया गया था। स्वागत के लिये दो दिन पहले ही सड़कों पर अभ्यास होने लगा था। स्वागत के लिये स्कूली बच्चों भी मौजूद थे।

सीएम योगी ने बद्रीकेदार दर्शन किये

देहरादून/रुद्रप्रयाग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड में भव्य स्वागत किया गया। सीएम पुष्कर धामी की अगुवाई में सीएम योगी का स्वागत किया गया। अपने कई कार्यक्रमों के बाद योगी ने बद्रीकेदार के दर्शन किये।

मुख्यमंत्री योगी ने केदारनाथ धाम में पूजा-अर्चना की। रात्रि विश्राम के बाद वह बदरीनाथ भी गये और भगवान बदरीविशाल के दर्शन कर पूजा की। अपने दौरे में योगी ने कहा कि वह धर्म की रक्षा के लिये लगातार अभियान बनाए हुए हैं। यूपी में अपराधियों पर अंकुश लगाया गया है। उत्तराखण्ड को जिस प्रकार से मदद की जरूरत होगी यूपी तैयार है।

मातृभूमि में योगी के स्वागत के लिये सरकार के मंत्रियों व भाजपा संगठन की ओर से भव्य तैयारियां की गई थीं। सभी मंत्री और दिग्गज उनसे मिले।

मिल्म्वालों की बैठक में नन्दा माता मन्दिर जीर्णोद्धार का निर्णय

जोहार। इस बार मिलम में माँ नन्दा पूजा के सुवसर पर मिलम पहुँचे सभी मिल्म्वालों ने गाँववासियों के संग मन्दिर परिसर में एक आमसभा का आयोजन किया। जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मिलम में माँ नन्दा माता के मन्दिर का जीर्णोद्धार किया जाय। इस पुनीत कार्य की जिम्मेदारी देवेन्द्र सिंह धर्मशक्तू को सर्वसम्मति से अध्यक्ष के रूप में चुनकर दी गई। अग्रणीय समाजसेवी और दृढ़ इच्छाशक्ति वाले देवेन्द्र सिंह धर्मशक्तू के संरक्षण में पूर्व में दरकोट मन्दिर निर्माण किया गया है। वर्तमान में वे कैची धाम व जागेश्वर धाम के सदस्य भी हैं। मिलम निवासियों के सभी गर्खाओं जैसे रावत, पांगती, धमोत, सयाना, निखुरपा, नित्वाल तथा शिल्पकार बन्धुओं से दो-दो सदस्य नियुक्त किया गया। जिसमें दिग्विजय सिंह रावत, भीम सिंह निखुरपा, लक्ष्मण सिंह पांगती, देव सिह नित्वाल, महिमन सिंह सयाना, चन्द्र राम, श्रीराम सिंह धर्मसक्तु, यतेन्द्र सिंह पांगती, भगत सिंह धमोत, नवीन सिंह पांगती, देवेन्द्र सिंह नित्वाल को सदस्य मनोनीत किया गया। अध्यक्ष ने उपस्थित लोगों को अवगत कराया कि जोहार महोत्सव हल्द्वानी में सभी मिल्म्वालो के साथ एक आम बैठक कर कार्यकारणी का गठन किया जाएगा। इस अवसर पर भूगर्भशास्त्री कुन्दनसिंह पांगती, डं. रणजीत सिंह धमोत जिन्होंने मिलम में सबसे पहले नये भवन का निर्माण किया है, दिग्विजय सिंह रावत जिन्होंने सबसे पहले पढाई पूरी कर मिलम में शिक्षित युवा के रूप में व्यवसाय शुरू किया, यतेन्द्र सिंह पांगती जी पूर्व निदेशक अर्थ एवं सांख्यिकी, भीम सिंह निखुरपा पूर्व जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी सहित मिलम की ध्यैनी श्रीमती पूजा जंगपांगी अध्यक्ष जे एस एस बागेश्वर ने अपने विचार रखें।

ओम पर्वत के दर्शन के साथ ही खूबसूरत नजारे

डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार का प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए हेलिकाप्टर सेवा शुरू करने पर फोकस है। आदि कैलाश समुद्रतल से 5945 मीटर की ऊँचाई पर स्थिति है। वेद पुराणों में आदि कैलाश भगवान शिव का सबसे प्राचीन निवास स्थल के रूप में प्रचलित है। पिथौरागढ़ जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल आदि कैलाश की यात्रा के लिए हेली सेवा की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए पर्यटन विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की अनुमति मिलने के बाद आदि कैलाश की यात्रा आसान होगी। अभी तक आदि कैलाश की पैदल यात्रा में कई दिनों का समय लगता है। साथ ही यात्रा काफी कठिन होती है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार का प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए हेलिकाप्टर सेवा शुरू करने पर फोकस है। आदि कैलाश समुद्रतल से 5945 मीटर की ऊँचाई पर स्थिति है। वेद पुराणों में आदि कैलाश भगवान शिव का सबसे प्राचीन निवास स्थल के रूप में प्रचलित है। इसे कैलाश मानसरोवर की प्रतिकृति माना जाता है। धारचूला से आदि कैलाश की यात्रा शुरू होती है। धारचूला से तवाघाट, पांगु, नारायण आश्रम, गाला, बूंदी, गर्ब्यांग, गुंजी, कुटी गाँव होते हुए अन्तिम पड़ाव ज्योलिकांग है। नाभीढांग से ओम पर्वत के दर्शन हो हैं। हिन्दू धर्म ग्रन्थों के अनुसार ब्रह्माण्ड का सृजन और उसके विनाश का जिम्मा सम्भालने वाले भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। भगवान शिव को सबसे बड़ा तपस्वी और भोला माना जाता है। उनके भक्तों की गिनती भी नहीं की जा सकती। हिन्दू मान्यताओं और पुराणों के अनुसार भगवान शिव हिमालय के कैलाश मानसरोवर पर वास करते हैं। माना जाता है कि शिव में तीन कैलाश पर्वत हैं, पहला कैलाश मानसरोवर जो कि तिब्बत में है, दूसरा आदि कैलाश जो उत्तराखण्ड में है और तीसरा है किन्नौर कैलाश जो हिमाचल प्रदेश में है। जहाँ तिब्बत, नेपाल और भारत की सीमाएं मिलती हैं, वहीं ओम पर्वत स्थापित है। वेदों में उल्लेख है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी और स्वर्ग के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। इस पर्वत श्रृंखला के चार मुख कम्पास की चार दिशाओं की ओर मुख किए हुए हैं। जैसा कि हिन्दू, जैन और बौद्ध मानते हैं, कैलाश पर्वत स्वर्ग का अन्तिम प्रवेश द्वार है। इसके अलावा, इसे पाण्डवों द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का स्थान भी माना जाता है, जो द्रौपदी के साथ इस चोटी पर ट्रैकिंग कर रहे थे। इस प्रकार, जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह आसानी से पुष्टि की जा सकती है कि निस्संदेह, कैलाश पर्वत रहस्यों का केन्द्र है जो अब तक अनसुलझे हैं प्राचीन भारतीय ग्रन्थों एवं पौराणिक कथाओं में आदि कैलाश को कैलाश मानसरोवर की प्रतिकृति के रूप में वर्णित किया गया है। धार्मिक मान्यताओं में इस स्थान की यात्र का फल कैलाश मानसरोवर के तुल्य माना जाता है। आदि कैलाश या छोटा कैलाश भारत के उत्तरी भाग में स्थित उत्तराखण्ड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। समुद्रतल से 5,945 मीटर की ऊँचाई पर स्थित आदि कैलाश दारमा, व्यास एवं चौदास घाटियों के मध्य स्थित है जहाँ आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ की अनुभूति होती है। यह स्थान भारत-तिब्बत बार्डर में भारतीय सीमा के अन्तर्गत आता है ऐसे में यहाँ जाने के लिए आपको ना तो किसी पासपोर्ट की आवश्यकता होती है एवं ना ही वीजा की। आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाए तो आदि कैलाश यात्रा काफी किफायती है एवं यहाँ जाने के लिए आपको अधिक कागजी झंझट करने की भी आवश्यकता नहीं है। पूर्ण रूप से भारतीय सीमा में पड़ने वाला यह पवित्र तीर्थ स्थल यात्रियों को कम व्यय में ही अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करता है जहाँ आप अपनी आध्यात्मिक क्षुधा को शाँत कर सकते है।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

पिघलता हिमालय

नियमों का बन्धन ही क्यों, सुविधा भी तो मिलनी चाहिये

मिशन की पत्रकारिता करने वालों के सामने चुनौतियां बराबर मिल रही हैं। नियमों में जकड़ते हुए कहीं इन्हें दबाने की कोशिश तो नहीं हो रही? प्रेस से जुड़े लोग इन दिनों में बेचैन दिखाई दे रहे हैं। असल में एक आदेश आया, जिसमें कहा है- 'प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, १८६७ की धारा ११ बी और समाचार पत्रों का पंजीकरण (केन्द्रीय) नियम, १९५६ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक प्रकाशक को अपने समाचार पत्र के एक अंक के प्रकाशन के ४८ घण्टे के भीतर भेजना होगा। प्रेस रजिस्ट्रार को अंक की एक प्रति डाक या सन्देशवाहक द्वारा भेजनी होगी। यह स्पष्ट किया गया है कि प्रकाशक धारा के तहत २००० रुपये तक का जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी हैं। यदि वे पीआरबी अधिनियम की धारा ११ ए और ११ बी के अनुपालन में समाचार पत्रों की प्रतियां वितरित करने में विफल रहते हैं, तो जन विश्वास अधिनियम, २०२३ द्वारा संशोधित पीआरबी अधिनियम की धारा १३ (VI) यह भी स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली स्थित पीआईबी/आरएनआई कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रतियों की डिलीवरी न होने को भी पीआरबी अधिनियम की धारा १२ के अनुसार पंजीकरण को निलंबित/रद्द करने का आधार माना जा सकता है। नियमित आधार पर प्रकाशन/प्रकाशन बंद करना। इसलिए, सभी प्रकाशकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि प्रकाशित समाचार पत्रों या पत्रिकाओं के प्रत्येक अंक की प्रतियां, जैसा भी मामला हो, प्रेस सूचना ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रलय, भारत सरकार के निकटतम क्षेत्रीय कार्यालय में जमा की जानी चाहिए। निर्धारित समय। एनसीआर दिल्ली में प्रकाशित समाचार पत्रों की प्रतियां भारत के समाचार पत्र रजिस्ट्रार के कार्यालय, सूचना भवन, नई दिल्ली में जमा की जानी चाहिए।'

वास्तव में देखा जाए तो यह आदेश के अलावा एक सच्चाई भी है। दरअसल होने यह लगा है कि समाचार पत्र की आड़ में कई ऐसे पत्र दिखाई दे रहे हैं जो व्यवहार में नहीं हैं बल्कि खानापूरी है। ऐसे में उन्हें बेचैनी हो सकती है। लेकिन इस कड़वी सच्चाई को भी जान लेना चाहिये कि छोटे-मझले समाचार पत्रों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है वह सौतेला कहा जायेगा। विज्ञापन नीति में इन्हें दबाया गया है। डाक व्यवस्था पहले के मुकाबले काफी सुस्त हो चुकी है और बार-बार कई जगह डाक न मिलने की शिकायतें मिलती हैं, ऐसे में कैसे मान लें कि आरएनआई या चाहे गये पते पर समाचार पत्र समय से मिल ही जाए। अच्छी बात है व्यवस्था बनाने और फर्जियाट रोकने के लिये सख्ती हो लेकिन जिन प्रकाशकों द्वारा मिशन के तहत कार्य किये जा रहे हैं उनके संरक्षण की ओर भी ध्यान देना चाहिये।

इन दिनों प्रेस से जुड़े लोंगों में जो चिन्ता और चर्चा हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि सरकार पता नहीं क्या करने जा रही है, देश में गिनती के कुछ ही अखबार रहेंगे। नया PIB एक्ट लागू हो गया। भारत में ५५० से ज्यादा ज़िले हैं। PIB के आफिस २९ हैं। उत्तराखण्ड, ओडिशा जैसे कई राज्यों में स्टाफ के नाम पर न्यूनतम ०१ और अधिकतम स्टाफ ०३ है। हर जिले में राज्य सरकार के सूचना कार्यालय स्थापित हैं, जहाँ रेगुलर रूप से सभी अखबार जमा होते हैं। लेकिन नए एक्ट ने इन कार्यालयों का वजूद समाप्त कर दिया। पहले किसी भी अखबार को अपने ज़िले के डीएम या डीसी के समक्ष एक घोषणा पत्र दाखिल करना होता था। ये अधिकार भी अब केन्द्र सरकार ने अपने पास ले लिया। अब ५५० ज़िले कैसे अपने अखबार की प्रतियां आरएनआई के २९ रीजनल आफिस में जमा करवाएंगे। दरअसल, सरकार चीन की तरह नागरिकों की आज़ादी को छीनना चाहती है। छोटे और मझोले अखबार पाकेट्स में जनमत का निर्माण करते हैं। सरकार इनसे डरी हुई है। कुछ बड़े अखबारों पर तो केन्द्र सरकार का नियंत्रण है लेकिन पाकेट्स को प्रभावित करने वाले हजारों छोटे, मझोले, क्षेत्रीय और भाषाई समाचार पत्रों पर सरकार का ज़ोर नहीं है। यदि हम उत्तराखण्ड की बात करें तो मध्यम समाचार पत्रों ने ही बहुगुणा सरकार, हरीश रावत सरकार और त्रिवेन्द्र सरकार के खिलाफ जनमत तैयार किया। हवाला घोटाला, राम रहीम, आशाराम जैसे तमाम मामलों में छोटे समाचार पत्रों ने ही माहौल तैयार किया।

समाचार पत्रों की नियमितता के लिये और उनके वास्तविक प्रकाशित होने की सच्चाई जानने के लिये कड़ाई को कतई गलत नहीं कहा जा सकता है लेकिन व्यवहार में यह भी होना चाहिये कि डाक द्वारा किस प्रकार प्रकाशित पत्र पहुँचे इसके लिये डाक विभाग को कहा जाए। साथ ही विज्ञापन या अन्य तरह से अखबारों के साथ सौतेला व्यवहार न किया जाए। यदि सख्ती के साथ न्याय भी मिलेगा तो बेहतर है अन्यथा पूरे देश के भीतर जो आक्रोश फैलेगा जिसकी कल्पना कर डर सा लगता है।

फसक

दाज्यू, पहाड़ी व्यंजन का मजा और ही ठैरा

भूकम्प और छात्र गुटों के मूड का पता नहीं चलता है बल

दाज्यू, भवाली में न्यायमूर्तियों की कार्यशाला में भोजन का षठरस पहाड़ी मटर, भट्ट की चुड़कानी, आलू के गुटके, झिंगोरे की खीर के रूप में था। भोजन व्यवस्था की जिम्मा कुमाऊँ मण्डल विकास निगम को था, सो निगम से झमाझम तैयारी कर दी। दाज्यू, पहाड़ी व्यंजन का मजा और ही ठैरा। हमें तो जम्मू-गन्द्रायणी-कालाजीरा तेजपत्ता-तिमूर के बिना कोई स्वाद ही नहीं लगता है। जड़ी-बूटी से सब हजम हो जाने वाला ठैरा। लेकिन आजकल सुन कौन रहा है? मैदे के ढीने तलकर घपाघप खाने का रिवाज फैल चुका है।

दाज्यू, स्वेरास्वेर बहुत बढ़ चुकी है तभी भूकम्प भी खूब आने लगे हैं बल। नेपाल को केन्द्र बनाकर धरती हिलते ही लोग सड़कों पर उतर आये। क्या पता प्रकृति के मूड को कौन जान सकता है। हम भी दुछत्ती पर बैठे थे, भूकम्प के झटके देख कूद मार दी। दाज्यू, प्राण तो बचाने ही हुए। खाया-पिया सब काफूर हो गया कहा। उसके बाद आलू के गुटके और रायता खाया। एनएसएस वाली मैडम कोलड्रिंक पीने को कह रही थी लेकिन हमें पचता ही नहीं है। दाज्यू, भूकम्प और छात्र गुटों के मूड का पता नहीं चलता है बल। सुना है, एमबी कालेज हल्द्वानी में कबीना मंत्री रेखा आर्या के सामने ही हंगामा मचा दिया। पुलिस ने भी ड्यूटी करनी हुई, दबोच डाले छात्र नेता। दाज्यू, छात्र संघ चुनाव तक छात्र गुट डोलते रहेंगे बल। नैनीताल के जूमलैंड क्षेत्र में भी डीएसबी कालेज के छात्रों के दो गुटों में लट्ठ चले। कलजुग में कौन किसकी बात मान रहा है? झूलाघाट में सड़क पर शराब पीने से मना करने पर युवक को चाकू घोंप दिया। पुलिस कह रही है- 'आरोपी गिरफ्तार हो गये हैं।'

दाज्यू, छात्र गुट छोड़ो, अब तो हर जगह गुट ही गुट हो रहे हैं। रुद्रपुर नगर पालिका के पूर्व सभासद रामबाबू ने नगर निगम के मेयर पर करोड़ों के घपले का आरोप लगा दिया है। बकायदा पत्रकार वार्ता भी कर दी। मेयर तो मेयर ही होने वाला हुआ। उनका कहना है- 'पूर्व सभासद नहीं चाहते हैं कि शहर का विकास हो।'

दाज्यू, सभासद और मेयर के झगड़े को छोड़ो। देखो, बड़े लोग क्या करने जा रहे हैं। उत्तराखण्ड सरकार को एक समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट रिपोर्ट एक माह में मिल जायेगी बल। सीएम पुष्कर गृहमंत्री शाह से मिल चुके हैं। दाज्यू, जोरदार होता जा रहा है। हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि उत्तराखण्ड के सरकारी स्कूलों में विदेशी विशेषज्ञ अतिथि संस्कार पढ़ाएंगे। दाज्यू, इंग्लैण्ड, हौलेण्ड, पौलेण्ड, न्यूजीलैण्ड, थाईलैण्ड बहुत सारे नाम सुने हैं इन्हीं में से कहीं के साब लोगों का करार होगा। पहाड़ी व्यंजन खिलाकर स्वागत होना चाहिये। इस बार से पहाड़ी करवाचौथ होगी बल। छत पर छन्नी लेकर चढ़ते हमने भी देखा पिछली बार। इस बार तो पूजा की थाली को ऐपण से सजाकर बाजार में लगा दिया गया है। दाज्यू, दुनिया एकदम हाईटैक होती जा रही है। भोजपुरी और पहाड़ी गीत का मिलाकर 'दौना लाइबो परवा बाज्यू, कमरिया तोरी' जैसा सुनाई दे रहा है।

हाईकोर्ट ने संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति के द्वारा हाईकोर्ट के पूर्व में दिए गए आदेश का अनुपालन नहीं करने पर उन्हें अवमानना नोटिस जारी कर दिया। दाज्यू, संस्कृत और संस्कृति पर हम क्या बोल सकते हैं? हाईकोर्ट का आदेश ठैरा। प्राइमरी व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति पाए करीब 3500 शिक्षकों की नियुक्ति पर जनहित याचिका में हाईकोर्ट ने पूछा है कि कितने फर्जी शिक्षक सस्पेंड किए हैं। अगली सुनवाई 23 नवम्बर को होगी बल। दाज्यू, किस किस को रोकें? बबली बता रही थी- 'कालेज में बुढ़िया गई विभाग वाली हैड बच्चों से चन्दा कर रही है। पीएचडी वालों की आँखे रो-रो कर सूख चुकी हैं। पता नहीं इतना पैसा लेकर कहाँ जाएगी।' दाज्यू, जमाना डबल-डबल करके बौइ गया है। उत्तराखण्ड में आते ही पहाड़ी व्यंजन यूपी में जाते ही देशी व्यंजन कहने वाले बहुत ठैरे। जिबड़ी की लपलपाट शान्त करना हर किसी के बस बात नहीं हुई। बबली को कौन समझाए कि छटमलाट की आग सुलगी रहती है। जितना लक्कड़ डालो उतना धुंआ छोड़ने वाली ठैरी।

सरकार ने इस बार 'गढ़भोज' आयोजन का आदेश दे डाला तो जगह जगह धपोड़ाधपोड़-सपोड़ासपोड़ हुई बल। पहाड़ी व्यंजन में धुपड्डुक-भात का मजा भी तो हुआ। लड्डन भी पहाड़ी में भाषण दे रहा था- 'ठीक छु, तम कस, मर ठीक।' दाज्यू, लड्डन की जवानी मैदान के बीहड़ में बीती है तो पहाड़ी भी उबड़-खाबड़ थी। जो हो रहा है होने दो दाज्यू। हम सेल्फी लेने काठगोदाम जा रहे है।। काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर चन्द्रयान-3 की थीम पर थ्रीडी सेल्फी प्वाइंट बनाया जा चुका है।

-तुम्हारा भुली झकरुवा

रेरा

विसंगतियों का कमेटी अध्ययन करेगी

हल्द्वानी। किसानों के बढ़ते आन्दोलन की धार देख मुख्यमंत्री के निर्देश पर तय हो चुका है कि रेरा की विसंगतियों का कमेटी अध्ययन करेगी। किसानों को दी गई अवधि के भीतर ही रेरा एक्ट की विसंगतियों के अध्ययन के लिये कमेटी गठन का शासनादेश जारी होने के बाद किसानों में आश जगी है।

नैनीताल जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनोन के निर्देश दिए हैं। इस कमेटी में 5 सरकारी अधिकारी व 6 जन प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह कमेटी रेरा एक्ट की विसंगतियों का अध्ययन करने के बाद 6 माह में शासन को रिपोर्ट सौंपेगी। सभी को पता है कि रेसा एक्ट की विसंगति को लेकर हल्द्वानी में किसानों ने 38 दिनों तक जबर्दस्त प्रदर्शन किया। कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने मामले को लेकर मुख्यमंत्री वार्ता की और किसानों के प्रतिनिधिमण्डल ने भी अपनी वार्ता की थी। पूरा मामले को समझते हुए सीएम ने रेरा की विसंगतियों के अध्ययन के लिये जिलाधिकारी नैनीताल वन्दना सिंह के नेतृत्व में 11 सदस्यी कमेटी गठित करने का आदेश दिया।

बिधायक बंशीधर भगत ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हुई वार्ता के दौरान जिन बातों पर सहमति बनी थी सभी पूरी कर ली गई हैं। वार्ता के अनुसार कमेटी गठित हो चुकी है। उन्होंने बताया कि अपर मुख्य सचिव आनन्दबर्द्धन एवं अपर सचिव अतर सिंह से फोन पर वार्ता में दोनों अधि कारियों ने बताया कि जिला प्रशासन को भी कमेटी की रिपोर्ट सौंपने तक की अवधि अगले 6 माह के लिये जमीनों की रजिस्ट्री पूर्व की भांति करने के आदेश दिये हैं।

इधर किसानों ने कहा है कि हमने वार्ता अनुसार आन्दोलन वापस लिया है और अब देखना है कि हमें व्यवहारिक दिक्कत न होने पाए।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

शिक्षा

केन्द्रीय विद्यालय क्यों नहीं खुले सरकार, चार साल पहले की थी पहल

डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला

केन्द्र सरकार ने चार साल पहले उत्तराखण्ड के हर ब्लाक में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की पहल की, जिसे आलवेदर रोड प्रोजेक्ट के बाद राज्य के लिए पीएम मोदी की दूसरी सबसे बड़ी सौगात माना गया, इसके लिए राज्य सरकार भी तय मानक के अनुसार मुफ्त भूमि उपलब्ध कराने के लिए तैयार थी। राज्य ने इसके लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा गया था। पत्र में कहा गया था कि इससे बच्चों को अपने ही क्षेत्र में बेहतर शिक्षा मिलेगी और पलायन रुकेगा। सवाल यह है कि इसके लिए जब सब तैयार थे, तो सरकार बताए कि केन्द्रीय विद्यालय क्यों नहीं खुले, इन विद्यालयों को खुलने में कमी कहाँ रह गई। राज्य में हर साल हजारों बच्चे केन्द्रीय विद्यालयों में पढ़ने का सपना देखते हैं, लेकिन सफल कुछ ही होते हैं। वर्ष 2019 में केन्द्र सरकार ने उत्तराखण्ड के हर ब्लाक में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की पहल की थी। केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली ने राज्य सरकार को तय मानक के अनुसार भूमि उपलब्ध कराने को कहा था। केन्द्रीय विद्यालय संगठन की ओर से कहा गया कि विद्यालय ढ़ाई से पाँच एकड़ परिसर में बनेगा। सरकार को एक रुपये की दर से 99 साल के पट्टे पर या मुफ्त भूमि उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा केन्द्रीय विद्यालय का स्थायी भवन बनने तक सरकार को मुफ्त में 15 कमरों की व्यवस्था करनी होगी, ताकि विद्यालय का अपना भवन बनने तक इसे अस्थायी भवन में शुरू किया जा सके। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पत्र के बाद शासन ने इस सम्बन्ध में सभी जिलों से प्रस्ताव मांगा, लेकिन केन्द्रीय विद्यालय नहीं खुल पाए। सत्ताधारी नेता कहते हैं- जनता की मांग है कि केन्द्रीय विद्यालय खुलने चाहिए, जहाँ जाता हूँ लोग इस बारे में पूछते हैं। हमने केन्द्र सरकार को विद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा था। केन्द्र का भी हमें पत्र आया था, इसे लेकर केन्द्र के जो मानक हैं उसमें शिथिलता दी जाए तो विद्यालय खुल सकते हैं। राज्य और केन्द्र सरकार को मिलकर केन्द्रीय विद्यालय पर काम करना था, स्कूल के कुछ मानक होते हैं, राज्य को ही स्थापना सुविधाएं खड़ी करनी होती हैं, इसमें कई बार व्यावहारिक दिक्कत आती है। इन्हें शुरू करने में कहीं कोई दिक्कत रहीं होगी। अभी इस बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा।

पूर्व केन्द्रीय शिक्षा मंत्री कहते हैं, उत्तराखण्ड केन्द्रीय विद्यालयों के लिए हमने कई प्रस्ताव भेजे हैं, इसमें कुछ मंजूर भी हुए हैं। इसके लिए मानक यह है कि उस क्षेत्र में केन्द्रीय कर्मचारी होने चाहिए। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने केन्द्र सरकार के निर्देश पर प्रवेश सम्बन्धी कुछ कोटे खत्म कर दिए हैं, जिनमें सांसद, मंत्री, चेयरमैन, डीएम के साथ ग्रैंड चिल्ड्रेन कोटा भी शामिल हैं। इस निर्णय के साथ ही केन्द्रीय विद्यालयों में इस साल करीब 40 हजार ऐसे बच्चों को प्रवेश नहीं मिल पया जो केन्द्रीय या रक्षा सेवा संवर्ग और शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के दायरे में नहीं आते हैं। कोटा सिस्टम खत्म करने के अपने-अपने पक्ष हैं, जो सही भी हैं, लेकिन बुनियादी सवाल यह भी है कि वे 40 हजार बच्चे कौन थे, जिन्हें इस कोटे से देश भर के केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिला मिलता था? क्या यह निर्णय वास्तविक अर्थों में संगठन की प्रवेश प्रक्रिया को समावेशी बनाने वाला है? बेशक तकनीकी रूप से यही लगता है, लेकिन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से शिक्षा दिलाने का सपना देखते है। बेहतर होगा कि केन्द्र सरकार आजादी के अमृत महोत्सव पर इस सच्चाई को स्वीकार करे कि देश में सीबीएसई और केन्द्रीय विद्यालय एक अति विशिष्ट शिक्षा तंत्र के रूप में खड़े हो गए हैं। आखिर क्यों स्वाधीनता के 75 साल बाद भी देश अपने नागरिकों को समुन्नत और जनाकांक्षाओं के अनुरूप समावेशी शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पा रहा है? क्या कारण है कि सात सौ से अधिक जिलों वाले इस देश में केवल 1,047 केन्द्रीय विद्यालय हैं? क्या अमृत महोत्सव में सरकार यह संकल्प नहीं ले सकती कि हर बड़े राज्य में 75 नए केन्द्रीय विद्यालय खोले जाएं? यह स्पष्ट है कि राज्य बोर्डों के मामले में 80 प्रतिशत बोर्ड फिसड्डी हैं। देश का आम आदमी मजबूरी में अपने बच्चों को राज्यों के स्कूलों में पढ़ाता है। वैसे इस बात को नीति नियोजक बखूबी समझते हैं। इसके बावजूद वे केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल जैसे नवाचारों पर चुप रहते हैं। सरकारें चाहें तो देश के प्रत्येक विकास खंड या तहसील इकाई पर भी केंद्रीय विद्यालय खोले जा सकते हैं। साथ ही डिफेंस, पैरा मेडिकल, विदेश मंत्रलय आदि के लिए एक अलग विंग स्थापित की जा सकती है। इन स्कूलों में प्रवेश के लिए आयकरदाता और आरटीई के प्रविधान अमल में लाए जा सकते हैं। केन्द्र सरकार चाहे तो राज्य सरकारों के तुलनात्मक रूप से बेहतर स्कूलों को केंद्रीय विद्यालय के रूप में भी अधिग्रहित कर सकती है। शिक्षा मंत्रे को यह सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि मौजूदा सीबीएसई पैटर्न आधारित शिक्षा देश के आम आदमी के लिए महंगी और दुरूह सपने जैसी ही है। हर आदमी अपने बच्चे को इसी पैटर्न में पढ़ाना चाहता है। इसके लिए वह हर स्तर पर त्याग करने को तैयार रहता है। सवाल यह है कि राज्यों की शैक्षणिक नाकामी के लिए क्या 75 साल के अनुभव अभी भी कम हैं? केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत को एक राष्ट्र-एक शिक्षा व्यवस्था के संकल्प की ओर उन्मुख करे। यह जो भेदभावपूर्ण शैक्षिक ढांचा है, उसे खत्म किया जाना चाहिए। अभी 11 लाख बच्चे केन्द्रीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। सरकार चाहे तो यह आंकड़ा प्रति वर्ष दो करोड़ भी हो सकता है। सवाल इच्छाशक्ति का है। उस हीनभाव को महसूस करने का है, जो करोड़ों बच्चे अपने घर, गली, स्कूल में सीबीएसई और राज्य बोर्ड के भेदभाव के चलते झेलते रहते हैं।

जोहार और जोहारी

जोहार हो जन्मभूमि
इसी भूमि में प्रयाण हो
जय जोहार वसुन्धरा
तेरी जय-जयकारा हो।
स्वर्ग भूमि, स्वर्ग लोक का
क्या कल्पना करता हूँ
इस भूमि से सुन्दर भूमि
धरती पर क्या और है।
स्वर्ण भूमि, रजत हिमालय
प्रात: काल का जो दृश्य
सामने अचल जो गिरि
चाँदी-सी फैली धवल
जहाँ बिछी स्वर्ण भूमि
शान्ति दूत निर्झर झरना
नीचे जो समतल भूमि
धरती पर देवताओं का वास
यही कहीं बस होगा।
जिस भूमि के थे मानव
नदारत कहाँ हो चले
कुछ तो सदा छोड़ चले
बहुत कुछ अब बिखर गए।
तू अजर, अमर, अमिट
हमें यूं बता रहा है
और जता भी रहा है
अभी हूँ, तू देख ले
पुरातत्व के भग्नावशेष का
एक पत्थर उठा लेना
अपने सीने से लगाकर
अपनों को याद कर लेना।
बहती माँ गोरी की सच्चाई
अभी भी बहते जा रही हैं
हे माँ! तेरी सन्तानें आज
आंहे भरकर सामने खड़े है।
माँ नन्दा तेरी छत्रछाया
पूरे क्षेत्र का आवरण हैं
तेरी ही कृपा दृष्टि से
जोहार का बचा अस्तित्व है।
जोहार ही हो जन्म भूमि
इसी भूमि पर प्रयाण हो।

-जगदीश बृजवाल

ज्योतिष की बातें - 148

18 अक्टूबर 2023 को सूर्य शत्रुराशि तुला में प्रवेश करेगा। वहाँ पर मंगल से युति होगी तो गुरु की दृष्टि भी रहेगी। अत: सूर्य की उग्रता गुरु से नियन्त्रित रहेगी। अगले एक माह सिंह, वृषभ, मकर, व धनु राशि के जातकों को सूर्य अपने कारक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पराक्रम, सफलता, यश प्राप्ति आदि विषयों में शुभफल प्रदान करेगा। अन्य राशि के जातकों को अभी प्रतीक्षा करनी चाहिए।

19 अक्टूबर 2023 को बुध अपनी उच्चराशि कन्या को छोड़कर मित्रराशि तुला में प्रवेश करेगा। इस अवधि में बुध सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य योग तो बनाएगा लेकिन अस्त भी रहेगा। अत: बुध अगले 18 दिन व्यवसाय, वाणिज्य, बुद्धि, आदि अपने कारक विषयों में कन्या, कर्क, वृषभ, मीन, मकर व धनु राशि के जातकों को अत्यन्त शुभ फल प्रदान करेगा। अन्य राशियों को भी सामान्य फल प्रदान करता रहेगा ।

शुभं भवतु !!

-ओंकार नाथ कोष्टा
ज्योतिर्विद् एवं आयुर्विद

सम्यक् विचार- 39

चुनाव और सरकारी कर्मचारी

जब भी चुनाव आता है, लगभग छ: महीने पहले से ही कर्मचारियों का स्थानान्तरण, प्रमोशन आदि रुक जाता है। लगभग तीन महीने पहले से चुनावी प्रशिक्षण का दौर शुरू हो जाता है। सरकारी कार्यों का कामकाज प्रभावित होता है। पोलिंग पार्टी के कर्मचारी अत्यधिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद चुनाव ड्यूटी में कभी-कभी तीन दिन तक निरन्तर व्यस्त रहते हैं और दो दिन तक तो कभी-कभी सोने को नहीं मिलता है। चुनाव के दिन बाजार बन्द रहता है, कर्मचारियों को उस दिन भोजन करने की भी दिक्कत आती है। जरा जरा सी बात पर कर्मचारियों को नौकरी चली जाने का भय दिखाया जाता है। प्रत्यक्ष चुनाव में लगे हुए कार्मिक अत्यन्त तनावग्रस्त रहते हैं। तीन महीने पहले से किसी प्रकार का अवकाश नहीं मिलता है, भले ही घर में किसी की शादी हो। वाहनों का अधिग्रहण हो जाने के कारण आम जनता को आवागमन में कई दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह परेशानी केवल पोलिंग पार्टी को ही नहीं बल्कि चुनाव में लगे सभी अधिकारियों तहसीलदार, जिलाधिकारी, कमिश्नर आदि को होती है। ईवीएम से चुनाव होने पर पहले की अपेक्षा अब अधिक ही प्रशिक्षण और जटिलता बढ़ गई है। और अब वीवीपेट मशीन भी आ जाने के कारण भयंकर जटिलता बढ़ चुकी है। पहले जहाँ 10-15 प्रपत्र भरे जाते थे वहाँ पर अब 40-50 प्रपत्रों को भरना पड़ता है।

चुनाव सुधार की बातें सभी करते हैं लेकिन जैसे-जैसे सुधार होता जाता है वैसे-वैसे कर्मचारियों का उत्पीड़न भी बढ़ता जाता है । देश में क्या कोई ऐसा नेता है जो चुनाव के नाम पर हो रहे कर्मचारियों के उत्पीड़न का विरोध कर सके?

-सरल

अखाड़ेबाजी

हल्द्वानी रामलीला मैदान की सम्पत्ति बनी और बची रहे

हल्द्वानी। अक्सर संस्थाओं के फलने-फूलने के बाद विवाद तब उत्पन्न होता है जब उसमें आय के स्रोत बन जाते हैं। साथ ही सम्पत्ति पर नज़र जमाये लोग अपनी सी करने लगते हैं।

ऐसा ही हल्द्वानी की प्रमुख रामलीला कमेटी का होने लगा है। वर्तमान में आरोप है कि प्रशासन इसका ट्रस्ट बनाना चाहता है। रामलीला कमेटी बचाओ संघर्ष समिति ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

बताते चलें कि हल्द्वानी में दिन की रामलीला का आकर्षण शुरू से रहा है। 140 साल पहले इस मेले की शुरुआत भाबर में जब हुई पहाड़ और मैदान के लोग प्रेमभाव से रामलीला मंचन देखने आते थे। शहर की रामलीला में पुतलों का नजारा और आपसी मेल-मिलाप का बहाना भी था। रामलीला में जुड़े लोग बहुत ही श्रद्धावान थे। यही कारण है कि बीच बाजार में बहुत बड़ा मैदान और मंच है। इससे लगा राममन्दिर है। धीरे-धीरे इस रामलीला मंचन के अलावा इसमें पैर जमाने के लिये कई लोग आतुर हो गये। नुमाइश व अन्य आयोजन भी होने लगे जो कमाई का जरिया थे। आगे चलकर विवाद भी बढ़ते रहे। पिछले समय में जैसे-तैसे रामलीला मंचन करवाया गया है। यही कामना है रामलीला मैदान की सम्पत्ति बनी और बची रहे।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

माउंट त्रिशूल पर तिरंगा फहराया

गोपेश्वर। कुमाऊँ रेजीमेंट के 14 सदस्यीय दल ने बीस साल बा माउंट त्रिशूल को फतह कर तिरंगा फहराया। यह दल रानीखेत से होते हुए सितम्बर माह में बेस कैम्प हेमकुण्ड पहुँचा। चोटी फतह करने में करीब बीस दिन का समय लगा। टीम लीडर कर्नल मनोज जोशी और मेजर आदित्य प्रकाश थे।

पालिका पर लगे आरोपों की जाँच

चम्पावत। नगर पालिका पर लगे आरोपों की जाँच डीएम द्वारा गठित तीन सदस्यीय टीम करेगी। भाजपा अनुसूचित मोर्चा जिलाध्यक्ष सूरज प्रहरी ने पालिका पर निर्माण कार्यों में धांधली, वार्डों में घटिया गुणवत्ता के कार्य कराने, बजट को गलत जगह खपाने, मनचाहे लोगों को ठेका देने, ठेकों के टेंडर की विज्ञप्ति स्थानीय अखबारों में न निकाल कर बाहरी पत्रिकाओं में निकालने के गम्भीर आरोप लगाए हैं।

पाटी में पानी के लिये हाहाकार

चम्पावत। पाटी लिफ्ट योजना दो हफ्ते में भी ठीक नहीं हो सकी जिससे क्षेत्र में पानी के लिये हाहाकार मच गया। नाराज क्षेत्रवासियों ने जल संस्थान के अपर सहायक अभियन्ता ज्ञापन देने के साथ ही प्रदर्शन किया।

बेरीनाग में सड़क निर्माण को धरना

बेरीनाग। पाताल भुवनेश्वर और सिमायल के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। ग्राम प्रधान नीमा वर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि पातालभुवनेश्वर-दौलावलिया-नैनीपातल-सिमायल से चामाचौड़ के बीच सड़क निर्माण की पुरानी मांग आज तक नहीं मानी गई है। ऐसे में ग्रामीण कई किमी की पैदल यात्रा करने को मजबूर हैं।

मरचूला, बिनसर में सुविधा विस्तार होगा

अल्मोड़ा। मरचूला, बिनसर, मानिला नए पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होंगे, इसके लिये वन विभाग तैयारी कर रहा है। इसमें पर्यटक आवास गृह बनने हैं और पहाड़ी व्यंजनों व साहसिक खेल शुरु होंगे।

पूर्णागिरी रोपवे दो साल में तैयार होगा

टनकपुर। पूर्णागिरी रोपवे दो साल में बनकर तैयार हो जायेगा। दिल्ली की कम्पनी ने इसका निर्माण कार्य शुरु कर दिया है। फिलहाल एलाइनमेंट के तहत झाड़ी कटान कार्य किया जा रहा है। रोपवे निर्माण से श्रद्धालुओं को पाँच किमी खड़ी चढ़ाई से राहत मिलेगी। वर्ष 2015 में तत्कालीन सीएम हरीश रावत ने रोपवे की घोषणा की थी।

कत्यूरी शैली में तैयार होगा माँ वाराही धाम का मुख्य मन्दिर

लोहाघाट। देवीधुरा स्थित प्रसिद्ध माँ वाराही धाम के मुख्य मन्दिर को कत्यूरी शैली में तैयार किया जायेगा। इसको लेकर बैठक आयोजित की गई। चार खाम व सात थोक के अलावा मन्दिर समिति अध्यक्ष व पुरोहित इस बैठक में शामिल हुए।

मन्दिर समिति के अध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में समिति के लोगों ने मन्दिर की संरचना उत्तराखण्ड के प्रसिद्ध मन्दिरों में प्रयुक्त कत्यूरी शैली का उपयोग करने पर जोर दिया। प्राचीन पूजा पद्धति जारी रखने पर बल दिया। तय किया गया कि खोलीखाड़, दुबचौड़ मैदान में किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा। गुजरात से आए वास्तुकार वर्षा शाह, चन्द्र बल्लभ टम्टा, दिलीप पांचाल, दिनेश जोशी भी बैठक में उपस्थित थे। वास्तुकारों की टीम ने देवीधुरा स्थित गब्यैरी, मचवाल, हनुमान मन्दिर, डोला सिंहासन, भीमशिला सहित अन्य मूर्तियों को भी निरीक्षण किया। बैठक में महादेव पुजारी, कीर्ति बल्लभ शास्त्री समेत पदाधिकारी उपस्थित थे।

नामिक में बुल्डोजर पहुँचा, सड़क बनेगी

बागेश्वर/नाचनी। आजादी के 73 वर्ष बाद सीमान्त क्षेत्र नामिक में सड़क बनने जा रही है। इसके लिये पहली बार बुल्डोजर पहुँचते ही लोगों ने स्वागत किया। थल-मुनस्यारी मार्ग पर बला से 27 किमी की दूरी पर स्थित नामिक तक पहुँचना बहुत कठिन ट्रेक है। मानसून के चार माह वर्षा और शीतकाल में हिमपात से यहाँ पहुँचना बेहद कठिन होता है। सड़क सुविधा के लिये क्षेत्र वासियों ने कई बार आन्दोलन भी किया था। वर्ष 2012 में विधानसभा चुनाव बहिष्कार भी किया गया। इसके बाद पीएम जीएसवाई के तहत होकरा से नामिक तक 17 किमी सड़क की घोषणा हुई। वर्ष 2018 में ग्राम होकरा से सड़क कटने का कार्य प्रारम्भ हुआ छह साल में नौ किमी सड़क ही कट सकी। दूसरी ओर नामिक की प्रधान तुलसी जैमियाल सड़क के लिये संघर्षरत रही। ऐसे में बागेश्वर जिले के गोगिना से नौ किमी सड़क कटने का कार्य हुआ। इसके बाद अब इस मार्ग से बुल्डोजर नामिक पहुँच सका है। अब उम्मीद है कि बागेश्वर जिला मुख्यालय से नामिक सड़क मार्ग से जुड़ पाएगा। नामिक बहुत ही मनोरम क्षेत्र है, जो यात्रा सुविधा न होने से छिटका था।

छावनी परिषद से मुक्ति को धरना

रानीखेत। छावनी परिषद से सिविल ऐरिया को अलग कर रानीखेत-चिलियानौला नगर पालिका परिषद में विलय करने की मांग को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन को 210 दिन से अधिक हो चुके हैं। रानीखेत विकास संघर्ष समिति के बैनर तले छावनी परिषद से आजादी की मांग को लेकर गांधी चौक पर पिछले काफी दिनों से धरना-प्रदर्शन जारी है। छावनी से मुक्ति के नारे लगाते प्रदर्शनकारी ऐलान कर चुके हैं कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती वह शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सुरम्य नगरी रानीखेत में पालिका होने से विकास कार्यों को गति मिलेगी। धरने में कैलाश पाण्डे, नरेन्द्र रौतेला, गिरीश भगत, जयन्त रौतेला, उमेश भट्ट, दीप भगत, चन्द्रशेखर मुनगली, दीपक गर्ग, हरीश अग्रवाल आदि शामिल थे।

मेयर का दावा ऐतिहासिक विकास

हल्द्वानी। मेयर डॉ. जोगेन्द्र रौतेला ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाने के लिये पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल में ऐतिहासिक विकास हुआ है। कहा निगम के पास आय के स्रोत न होने से कर्मचारियों का वेतन देना भी मुश्किल था लेकिन आज आय में दिन-प्रतिदिन बढ़ोत्तरी हो रही है। निगम अब तक 40 करोड़ रुपये से सड़कों का निर्माण करा चुका है।

उन्होंने बताया कि शहर में 370 करोड़ रुपये से ग्रीन तहसील भवन का निर्माण कराया जाएगा। नए तहसील भवन में 450 वाहनों की पार्किंग के अलावा सीनियर सिटीजन के लिए स्पेस, पत्रकारों के लिए कक्ष, ऑडिटोरियम तथा मीटिंग हॉल होगा। इसके निर्माण के लिये कार्यवाही गतिमान है। मेयर ने यह भी कहा कि केन्द्र से मिले 2200 करोड़ के विशेष पैकेज के अन्तर्गत पनचक्की चौराहे का नवनिर्माण होगा। इसके साथ ही शहर के 22 चौराहों का कायाकल्प होगा।

अस्कोट खेल मैदान को रहने भी दो

अस्कोट। नगर के खेल मैदान में आईटीआई भवन निर्माण से आमजन में आक्रोश है। क्षेत्रवासियों ने निर्माण कार्य रुकवाते हुए कहा कि 'अस्कोट खेल मैदान को रहने भी दो।' उनका कहना है कि इलाके भर की खेत प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिये व किसी आयोजन के लिये एकमात्र खेल मैदान है, उसे किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य करवाकर बर्बाद नहीं किया जाना चाहिये।

क्षेत्र पंचायत सदस्य विवेक भण्डारी और हिनकोट के प्रधान बहादुर बिष्ट के नेतृत्व में ग्रामीणों ने खेल मैदान में खुदाई कर रहे मजदूरों को कार्य करने से रोक दिया। कहा कि आईटीआई प्रशासन के पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। बावजूद इसके उक्त भूमि पर भवन निर्माण कार्य कर खेल मैदान को बिगाड़ा जा रहा है। ग्रामीण उत्थान समिति के संयोजक तरुण पाल, वीरजंग पाल, राजेश भट्ट ने कहा कि यह किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे।

उक्रांद ने जिला प्रभारी बनाए, बदलाव

देहरादून। उत्तराखण्ड क्रान्ति दल ने जिला प्रभारियों की नियुक्ति करते हुए संगठन को मजबूती का अभियान चलाया है। अध्यक्ष पूरण सिंह कठैत ने पद संभालते ही पार्टी संगठन में पहला बड़ा बदलाव जिला प्रभारियों की नियुक्ति के रूप में किया है।

केन्द्रीय अध्यक्ष पूरण सिंह कठैत ने बताया कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने को पहले चरण में जिला प्रभारी नियुक्त किये गए हैं। इसके बाद नगर, ब्लाक, न्याय पंचायत से लेकर बूथ प्रभारियों को नियुक्त किया जायेगा। दिल्ली की जिम्मेदारी प्रताप शाही, सह प्रभारी डॉ. बिहारी लाल जालंधरी को दी गई है। हरिद्वार में बहादुर सिंह रावत, देहरादून में रविन्द्र बशिष्ठ, उत्तरकाशी में जयप्रकाश उपाध्याय, टिहरी पंकज व्यास, पौड़ी महेन्द्र रावत, चमोली राजेन्द्र बिष्ट, उधमसिंह नगर आनन्द सिंह असगोला, नैनीताल सुनील उनियाल, बागेश्वर भुवन जोशी, चम्पावत शिवसिंह रावत, अल्मोड़ा इन्द्र सिंह मनराल, पिथौरागढ़ रमेश थलाल, डीडीहाट भानू मेहरा को जिम्मेदारी दी है।

नौ सूत्री मांगों को लेकर उपवास

श्रीनगर। क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रगतिशील जन मंच का धरना जारी है। नौ सूत्री मांगों को लेकर अनिल स्वामी भी एक दिन के अपवास पर बैठे। कहा कि जब तक मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है, तब तक उनका आन्दोलन जारी रहेगा। धरने को विभिन्न संगठनों का समर्थन मिल रहा है।

घिमतोली के गाँव विकसित होंगे

रुद्रप्रयाग। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत केदारनाथ विधायक शैलारानी रावत ने घिमतोली क्षेत्र में पहुँची। उन्होंने स्वारी-ग्वास स्थित अमृत सरोवर का का अनावरण किया। राजकीय इण्टर कालेज में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी करते हुए विधायक ने कहा कि घिमतोली क्षेत्र का नैसर्गिक सौन्दर्य आज देश-विदेश में पहचान बना रहा है। भगवान कार्तिक स्वामी मन्दिर का मुख्य पड़ाव होने के कारण श्रद्धालुओं का लगाव है। इसे पर्यटन गाँव के तौर पर विकसित किया जायेगा।

परिक्रमा

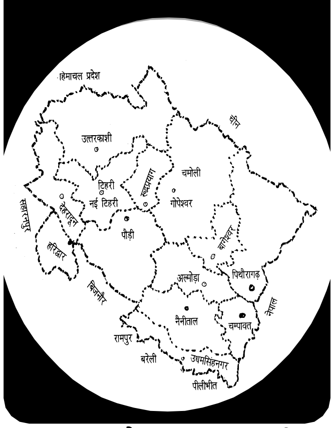

पेड़ कटान की एसआईटी जाँच

देहरादून। चकराता और पुरोला टोंस वन प्रभाग में हरे पेड़ काटे जाने के मामले में एसआईटी जाँच होगी। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने निर्देश दिये हैं कि बीते दिनों चकराता वन वन प्रभाग में देवदार के सैकड़ों पेड़ काटे जाने का खुलासा हुआ था। मामले में डीएफओ को हटाते हुए कई अधिकारी कर्मयारियों को निलम्बित कर दिया गया है।

जागेश्वर मंदिर अध्यक्ष को आयोग का नोटिस

अल्मोड़ा। जागेश्वर मन्दिर प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष व लोक सूचना अधिकारी को समिति के आरटीआई के दायरे में न आने पर सूचना आयोग ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राज्य सूचना आयोग ने सम्बन्धित को 8 नवम्बर इसके लिखित उत्तर के साथ पेश होने के आदेश दिये हैं। असल में जुलाई में प्रबन्ध समिति ने आरटीआई दायरे में शामिल न होने का हवाला दिया था।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

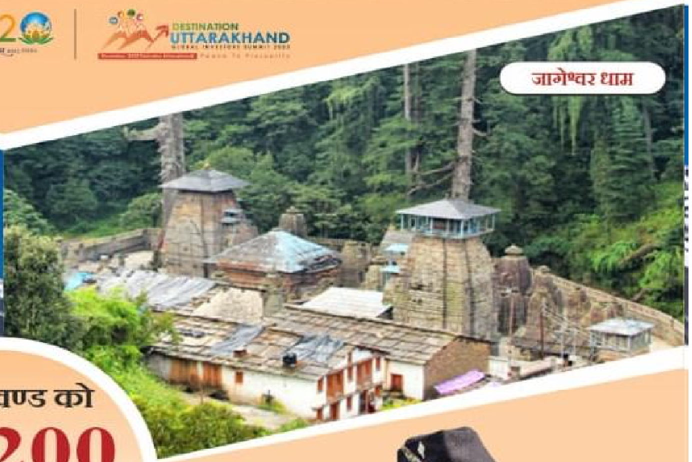

उत्तराखण्ड को ₹ 4200 करोड़ की परियोजनाओं का उपहार

इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल, खेल एवं पर्यटन, आपदा प्रबंधन, बागवानी से जुड़ी कुल 23 विकास परियोजनाओं का

उत्तराखण्ड को महत्व देने के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। हम निश्चित रूप से मोदी जी की आकांक्षाओं का उत्तराखण्ड बनाएंगे। प्रदेश के लिए उनका योगदान वृहद एवम् महत्वपूर्ण है। उत्तराखण्ड से उनका रिश्ता मर्म एवं कर्म का है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, विरासत पर गर्व और दूसरा, विकास के लिए हरसंभव प्रयास। आज उत्तराखंड, इन दोनों ही स्तंभों को लगातार मजबूत कर रहा है।

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

लोकार्पण एवं शिलान्यास

प्रधानमंत्री
नरेन्द्र मोदी
के कर कमलों द्वारा

शिलान्यास
₹ 2845 करोड़ की 13 परियोजनाएँ

किसानों की आय में होगी वृद्धि
- 21398 पॉली-हाउस निर्माण की योजना
- उच्च घनत्व वाले सघन सेब बागानों की योजना

इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास
- राष्ट्रीय राजमार्गों पर 02 लेन एवं ढलान उपचार के 05 कार्य
- राज्य में 32 पुलों का निर्माण

आपदा प्रबंधन को मजबूती
- एसडीआरएफ के तहत अग्नि सुरक्षा बुनियादी ढांचे और बचाव उपकरणों को मजबूत करना
- देहरादून में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) का अपग्रेडेशन
- बलियानाला, जनपद नैनीताल में भूस्खलन की रोकथाम हेतु उपचार

शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं का विस्तार
- 20 मॉडल डिग्री कॉलेजों में हॉस्टल और कंप्यूटर लैब का निर्माण
- सोमेश्वर, अल्मोड़ा में 100 बिस्तरों वाला उप जिला अस्पताल
- चंपावत में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल ब्लॉक का निर्माण
- रूद्रपुर में वेलो-ड्रोम निर्माण कार्य
- स्पोर्ट्स स्टेडियम, हल्द्वानी में एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान का निर्माण

चार धाम की भांति मानसखंड के मंदिर क्षेत्रों का विकास
- मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत जागेश्वर धाम, हाट कालिका एवं नैना देवी मंदिर में अवस्थापना सुविधाओं का विकास

लोकार्पण
₹ 1349 करोड़ की 10 परियोजनाएँ

इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास
- पीएमजीएसवाई के तहत 76 सड़कें
- पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 25 पुल
- 09 जिलों में 15 ब्लॉक कार्यालय भवन
- केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत 03 सड़क सुदृढीकरण कार्य
  - कौसानी - बागेश्वर रोड
  - धारी - डोबा - गिरेछिना रोड
  - नगला - किच्छा एस एच रोड डबल लेन
- राष्ट्रीय राजमार्गों को 2 लेन एवं सुदृढीकरण करने का कार्य
  - एन एच 309 बी - अल्मोड़ा - पेट्सल - पनुआनौला - दन्या
  - एन एच - टनकपुर - चल्थी
- प्रदेश में 39 पुल एवं देहरादून में यूएसडीएमए भवन

पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल और बिजली सुविधाओं की उपलब्धता
- 38 ग्रामीण पंपिंग पेयजल योजनाएं और 03 ट्यूबवेल आधारित पेयजल योजनाएं
- 419 ग्रामीण ग्रेविटी पेयजल योजनाएं
- थरकोट, पिथौरागढ़ में कृत्रिम झील
- 132 केवी पिथौरागढ़-लोहाघाट-चंपावत ट्रांसमिशन लाइन

गरिमामयी उपस्थिति

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

अजय भट्ट
केंद्रीय राज्य मंत्री

मंत्री, उत्तराखंड सरकार
सतपाल महाराज
गणेश जोशी
प्रेमचंद अग्रवाल
सुबोध उनियाल
डॉ. धन सिंह रावत
रेखा आर्या
सौरभ बहुगुणा

सांसद
डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक'
अजय टम्टा
कल्पना सैनी
नरेश बंसल
रेखा वर्मा

12 अक्टूबर, 2023 (बृहस्पतिवार)
समय : अपराह्न 2:30 बजे

स्थान : श्री सुरेन्द्र सिंह वल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम, पिथौरागढ़

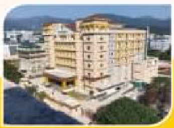

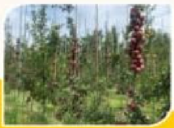

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी
www.uttarainformation.gov.in uttarakhandDIPR DIPR_UK uttarakhand DIPR

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

जोशीमठ पुनर्वास कार्य पीएमओ की निगरानी में

देहरादून। भूधंसाव से घिरे जोशीमठ की सुरक्षा और पुनर्वास के लिये केन्द्र सरकार ने राज्य के आर्थिक प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए 1845 करोड़ रुपये की सहमति दी है। यह कार्य पीएमओ की निगरानी में होंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उच्चस्तरीय बैठक में जोशीमठ के पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए बातचीत हुई। जोशीमठ में अलकनन्दा और धौलीगंगा के कारण हो रहे इलेजन को रोकने के लिये सिंचाई विभाग डीपीआर तैयार कर चुका है। हाइस्लिक जोन से सभी लोगों को विस्थापित किया जाएगा।

बताते चलें कि प्रदेश सरकार ने जोशीमठ मामले में पोस्ट डिजास्टर नीड एसेस्मेंट रिपोर्ट तैयार करते हुए केन्द्र सरकार से 1845 करोड़ रुपये की मांग की थी। गृह मंत्रालय की ओर से संकेत मिलने के बाद जोशीमठ पुनर्वास कार्य शुरु होने का रास्ता खुल चुका है। आपदा प्रबन्धन सचिव के अनुसार इसमें भूमि अधिग्रहण के लिये आवश्यक 91 करोड़ रुपये और बांकी 1754 करोड़ रुपये के 10 प्रतिशत राशि की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी है। शेष 1578 करोड़ रुपये की सहायता राशि केन्द्र सरकार करेगी।

इनर लाइन की सीमा तक बिना परमिट के जा सकेंगे पर्यटक

जिला पंचायत सदस्य जगत ने उठाया था मामला

पिथौरागढ़। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने भी (लाकुरीभेल नामक स्थान) इनर लाइन तक बिना अनुमति के पर्यटकों तथा स्थानीय निवासियों को जाने की अनुमति दे दी है। इस आदेश के बाद चीन सीमा से लगे मल्ला जोहर तथा रालम क्षेत्र में पर्यटन व्यवसाय के बढ़ाने की उम्मीद है।

यहाँ पर बता दें कि भारत सरकार के स्पष्ट शासनादेश के बाद भी इनर लाइन की सीमा के भीतर पर्यटकों को जाने के लिए अनुमति पत्र बनाने की परम्परा लम्बी समय से चल रही थी। अनुमति पत्र बनाने की प्रक्रिया लम्बी तथा कठिन होने के कारण पर्यटकों के दस्ते मीलम ग्लेशियर सहित अन्य पर्यटक स्थलों का भ्रमण नहीं कर पा रहे थे। पर्यटकों के कई दस्ते परमिट नहीं बन पाने के कारण वापस लौट जाने से पर्यटन व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने इस मामले को जिलाधिकारी रीना जोशी के सम्मुख को उठाया। जिला-धिकारी द्वारा दिए गए आदेश के बाद उप जिलाधिकारी मुनस्यारी ने प्रस्ताव बनाकर सेनानी चौदवीं वाहिनी वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस जाजरदेवल को भेजा। सीमा पुलिस के उप सेनानी रोबिन कुमार ने आदेश पत्र जारी करते हुए सीमा पुलिस के मुनस्यारी से लेकर मीलम तक की चौकियों को आदेश कर दिया है कि भारत सरकार के शासनादेश के अनुसार पर्यटकों तथा स्थानीय नागरिकों को बिना अनुमति के इनर लाइन तक की सीमा तक जाने की अनुमति दी जाती है। इस आदेश के बाद पर्वतारोहण, पथारोहण तथा अन्य साहसिक पर्यटन के लिए आने वाले पर्यटकों को परमिट की झंझट से निजात मिल गयी है। इससे आने वाले समय में पर्यटन की गतिविधियां बढ़ेगी। जिला पंचायत सदस्य जगत सिंह मर्तोलिया ने कहा कि मुनस्यारी में शीघ्र स्थानीय होटल, रेस्टोरेंट,होमस्टे, पोर्टस, गाइड, तथा टूर एंड ट्रेक चलाने वाले युवाओं की एक बैठक आयोजित की जा रही है। कहा कि मुनस्यारी क्षेत्र में आने वाले मेहमानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। इस बात को लेकर क्षेत्र में टूरिज्म के नए कल्चर का निर्माण किया जाएगा।

इस बार अक्टूबर में 'जोहार महोत्सव'

हल्द्वानी। जोहार सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अपनी संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिये किये जाने वाले जोहार महोत्सव को इस बार 28 व 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इसके लिये समिति द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सांस्कृतिक सचिव नरेन्द्र टोलिया ने आयोजन की रूपरेखा बनाते हुए इसे सफल बनाने की अपील की है। कैलाश सिंह धर्मशक्तू ने बताया कि पहले दिन कविता लेकर, जोहारी संस्कृति आधारित क्विज, महेंदी व वेशभूषा प्रतियोगिता के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। दूसरे दिन बच्चों की कक्षावार चित्रकला, सामान्य ज्ञान पर आधारित क्विज/भाषण प्रतियोगिता, फैन्सी ड्रेस शो, शौका व्यंजन प्रतियोगिता के अलावा ढुस्का-चांचरी महिला-पुरुष होंगे।

मल्ला दुम्मर में हरि प्रदर्शनी के लिये तैयारियां

मुनस्यारी/हल्द्वानी। हरि स्मारक समिति द्वारा प्रतिवर्ष मल्ला दुम्मर में होने वाली हरि प्रदर्शनी की तैयारियां शुरु हो चुकी हैं। 5, 6 व 7 नवम्बर को जोहार क्षेत्र के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व.हरिसिंह जंगपांगी की याद में होने वाले तीन दिवसीय आयोजन में मुख्य रूप से अपने कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाता है। क्षेत्र की प्रतिभाओं को अवसर देने के साथ ही मल्ला दुम्मर सहित आस-पास सभी गाँवों का हमेशा से इस आयोजन के लिये उत्साह रहा है।

जंगपांगी बन्धुओं की जागरूकता का परिणाम है कि हरि स्मारक समिति आजादी के बाद से लगातार अपने दम पर सीमान्त क्षेत्र की इस प्रदर्शनी को नियमित रूप से कर रही है। इसके लिये किसी भी तरह की सरकारी सहायता आज तक नहीं मिली है लेकिन अपनी संस्कृति और अपने स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण करने के लिये हरि सिंह जंगपांगी की याद में होने वाला आयोजन मेले का रूप ले चुका है। अच्छी बात यह भी है कि इस आयोजन को अपसंस्कृति से बचाने के लिये सयाने लोग सक्रिय हैं। इसमें स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित किया जाता है। क्षेत्रवासियों सहित के यत्र-तत्र नौकरी पेशा व बस चुके लोगों को हर बार इस प्रदर्शनी का इन्तजार रहता है।

चौदास का कंडाली भाम २४ अक्टूबर से

धारचूला। चौदास घाटी में 12 वर्ष के अन्तराल में होने वाला कण्डाली भाम 24 अक्टूबर से होगा। जिसमें अनुपयोगी, अवगुणी और अभिशप्त मानी जाने वाली कण्डाली घास को नष्ट किया जाता है।

12 वर्ष बाद दशहरे के पर्व पर मनाए जाने वाले कण्डाली पर्व के दौरान गाँव की महिलाएं दन-कालीन में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी और पुरुष तलवार से एक पवर्ष में एक-एक गांठ बढ़कर 12 वर्ष में 12 गांठ वाली बनी कण्डाली घास को नष्ट करेंगे। रं समाज प्रतिवर्ष दशहरे में स्यंठ त्यौहार मनाता है। बताते चलें कि चौदास के रं लोग शुक्रवार और रविवार को अपने देवस्थलों में पूजा नहीं करते हैं। इन दो दिनों में पूजा वर्जित रहती है। सदियों की इस परम्परा में स्यंठ पूजा में पहले दिन घरों के बर्तनों की सफाई होती है, दूसरे दिन सभी देवस्थलों पर समाज के नियमानुसार पूजा-पाठ की जाती है। तसीरे और चौथे दिन प्रत्येक गाँव के कई परिवारों में प्रथम बालक का सभा संस्कार होता है। इसे रं संस्कृति की परम्परा अनुसार ही मनाया जाता है। इसी क्रम में 12 वर्ष बाद कण्डाली उत्सव के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इस वर्ष में रं समाज के किसी भी बालक का सभा संस्कार नहीं किया जाता है।

मान्यता है कि प्राचीन समय में चौंदास घाटी में एक परिवार में एक ही बालक घर का चिराग था। जब वह 12 वर्ष का हुआ असाध्य रोग से घिर गया। जैसा कि माना जाता है कि हिमालय में उगने वाली सभी वनस्पतियां औषधि हैं, इसी आधार पर बालक का उपचार होने लगा। कण्डाली पौधे से भी उपचार किया गया तो बालक की मृत्यु हो गई। दु:खी माता-पिता ने कण्डाली को श्राप दिया कि 12 वर्ष बाद 12 गांवों में पुष्कर खिलेंगे तो तुम्हारी भी मृत्यु हो जायेगी। तभी से कण्डाली को अवगुणी पौधे के रूप में जानते हुए नष्ट किया जाता है।

Hotel
Bala Paradise
Tiksain, Munsiari
Ph. 05961222237, 9412951678

Hayat Paradise
Bus Station
Munsiari
Ph. 09411556700, 9997733070

माँ नन्दा आयरन एण्ड बिल्डिंग
मैटेरियल, भोटिया पड़ाव, हल्द्वानी
(सीमेन्ट, सरिया, टाइल, पेण्ट, सेनेटरी, हार्डवेयर)
गोदाम- जोहार एसोसिएट्स
बच्चीनगर- 1, कमलुवागांजा, हल्द्वानी
मो.- 7409440813, 7500619761

MARTOLIA
FURNITURE
A unit of Martolia Enterprises
Pilikothi, Haldwani
Mob- 8057167777, 7906752084, 8650427229

धमोत होम स्टे
धरमघर/चकोड़ी
(एडवेंचर जोन, ट्रेकिंग,माउंटेन वाइकिंग, स्थानीय व्यंजन)
मो. 9760007148
www.mountainheights.in

होटल माँ नन्दादेवी एण्ड बारातघर
नानासेम, मुनस्यारी
गणेश सिंह मर्तोलिया एण्ड सन्स
हार्डवेयर, बिल्डिंग मैटीरियल, जनरल आर्डर सप्लायर्स
फोन सम्पर्क- 05961-222236
8958525979, 9411134775

Enjoy Beauty of Himalaya at
MARTOLIA LODGE
Family Guest House- Sarmoly, Munsiyari
A Home Away From Home & Home Stay
Phone: (05961) 222287

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक श्रीमती गीता उप्रेती द्वारा पिघलता हिमालय, जे०के०पुरम्, सेक्टर डी, छोटी मुखानी, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड से प्रकाशित एवं शक्ति प्रेस, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) से मुद्रित।
सम्पादक: श्रीमती गीता उप्रेती फोन/फैक्स: (05946) 264013, 9458961490, 9411770280, 9411301014, 9410713075,
editorpighaltahimalay@gmail.com
Website- www.pighaltahimalay.com
पत्र व्यवहार के लिये पते- जे0के0पुरम्, सेक्टर डी, छोटी मुखानी, हल्द्वानी(नैनीताल)

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)